

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3647
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

+3647. श्री राजेश रंजन:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है,
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत किसानों की स्थिति में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के साथ-साथ व्यापक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि संबंधी समग्र गतिविधियां शामिल हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करता है:

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
3. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
4. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
5. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
6. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
7. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि' (एग्रीश्योर)

केंद्र प्रायोजित योजनाएं:

(क): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

(ख): कृषोन्ति योजना जिसमें शामिल है:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयलपाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)
4. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
5. डिजिटल कृषि मिशन
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
7. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमई)
8. समेकित कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
9. समेकित कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)

(ग): राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जिसमें शामिल है:

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएम) (फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) सहित)
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिनमें से कई सफल किसानों की आय में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2022-23) में एक विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना इस प्रकार है:

क्षेत्र	विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रुपये)	
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2022-2023
ग्रामीण	1,430	3,773
शहरी	2,630	6,459